भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1875
दिनांक 31 जुलाई 2025

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें

†1875 **श्री के. राधाकृष्णन:**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान देशभर में पेट्रोल, डीजल और घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की वार्षिक खुदरा कीमतें क्या रही है;

(ख) वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अदानी टोटल गैस लिमिटेड सहित प्रमुख सरकारी और निजी क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ कितना है;

(घ) क्या सरकार ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के मुद्रास्फीति और आम नागरिकों के जीवन-यापन की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई अध्ययन कराया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार ईंधन मूल्य निर्धारण तंत्र को विनियमित करने, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए कोई उपाय करने का प्रस्ताव कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): वर्ष 2015-16 से पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी (दिल्ली में) के वार्षिक औसत खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) के ब्यौरे अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ): पेट्रोल और डीजल के मूल्य बाजार निर्धारित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से जुड़े हुए हैं। भारत अपने कच्चे तेल की 85% से भी अधिक की आवश्यकताओं का आयात करता है। कच्चे तेल के मूल्य (भारतीय बास्केट) 55 डॉलर/बीबीएल (मार्च 2015) से बढ़कर 113 डॉलर/बीबीएल (मार्च 2022) तथा आगे और अधिक बढ़ कर 116 डॉलर/बीबीएल (जून 2022) हो गए और विभिन्न भूराजनीतिक एवं बाजार कारकों के कारण अत्यधिक अस्थिर बने हुए हैं, जबकी सरकार और पीएसयू ओएमसीज द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप घरेलू तौर पर पेट्रोल और

डीजल के मूल्य नवंबर 2021 में 110.04 रुपए तथा 98.42 रुपए प्रति लीटर से कम होकर क्रमश: 94.77 रुपए और 87.67 रुपए प्रति लीटर (दिल्ली मूल्य) हो गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर दो बार नवंबर 2021 और मई 2022 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमश: कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की गई थी, जिसका लाभ पूरी तरह से उपभोक्ताओं को दे दिया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य वैट दरें कम कर दी। मार्च, 2024 में, ओएमसीज ने पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक के खुदरा मूल्यों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी की। अप्रैल 2025 में पेट्रोल और डीजल, प्रत्येक पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई परंतु इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया।

हाल ही में पीएसयू-ओएससीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है। इसमें राज्यों के भीतर सुदूर भागों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी के रूप में पेट्रोलियम ऑयल और ल्युब्रिकेट्स (पीओएल) डिपो से दूर रहने वाले उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इस पहल ने एक राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के बीच का अंतर भी कम कर दिया है।

सरकार ने आम नागरिकों को उच्च अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से बचाने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि शामिल थे।

सरकार ने कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों जिसमें- घरेलू अन्वेषण तथा कच्चे तेल उत्पादन में बढ़ोत्तरी, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, भारतीय उर्जा बास्केट में नवीकरणीय स्रोतों की साझेदारी में सुधार आदि शामिल हैं, के प्रभाव पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं।

भारत घरेलू एलपीजी के खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े हुए हैं। औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 51 % (जुलाई 2023 में यूएस अमेरीकी डॉलर 385 प्रति एमटी से जून 2025 में यूएस अमेरीकी डॉलर 582 प्रति एमटी तक) तक वृद्धि हुई है जबकि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी के प्रभावी मूल्य में 38% (अगस्त 2023 में 903 रूपए से जुलाई, 2025 में 553 रुपए तक) की कमी की गई।

वर्तमान में 14.2 किलोग्राम वाले एक घरेलू एलपीजी सिलिंडर का खुदरा बिक्री मूल्य दिल्ली में 853 रुपए है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपए प्रति सिलिंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 553 रुपए प्रति सिलिंडर (दिल्ली में) की प्रभावी लागत पर 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करवा रही है। यह पूरे देश में लगभग 10.33 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध हैं।

पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी के मूल्यों में वृद्धि/कमी का आकलन थोक, मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति पर उनके प्रभाव के माध्यम से किया जा सकता है। डब्ल्यूपीआई सूचकांक में पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी का भारांक क्रमशः 1.60%, 3.10% और 0.64% है।

वर्ष 2015-16 से पीपीएसी द्वारा संकलित तेल एवं गैस क्षेत्र की सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के स्टैन्डएलोन कर-पश्चात लाभ (पीएटी)/हानि का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें " के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को श्री के. राधाकृष्णन द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न स. 1875 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्तीय वर्ष	खुदरा बिक्री मूल्य (दिल्ली में)		
	पेट्रोल (रु./लीटर)	डीज़ल (रु./लीटर)	घरेलू एलपीजी (रु./14.2 किलोग्राम सिलिन्डर)
2015-16	61.59	47.01	586.09
2016-17	64.61	53.24	554.17
2017-18	69.2	58.78	657.41
2018-19	75.37	68.22	754.33
2019-20	72.69	65.78	688.03
2020-21	80.84	73.58	650.80
2021-22	98.05	87.42	866.85
2022-23	97.9	90.58	1,038.70
2023-24	96.63	89.53	979.23
2024-25	94.74	87.64	803.00
2025-26 (23.07.2025 तक)	94.77	87.67	847.26

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

अनुलग्नक-II

"पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें " के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को श्री के. राधाकृष्णन द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न स. 1875 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

तेल और गैस कंपनियों का स्टैन्डएलोन कर पश्चात लाभ (पीएटी) / (हानि)

वित्तीय वर्ष	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	अदानी टोटल गैस
2015-16	11,242	7,056	3,725	27,426	*एनए
2016-17	19,106	8,039	6,209	31,425	*एनए
2017-18	21,346	7,919	6,357	33,612	165
2018-19	16,894	7,132	6,029	35,163	229
2019-20	1,313	2,683	2,637	30,903	436
2020-21	21,836	19,042	10,664	31,944	472
2021-22	24,184	11,363	6,383	39,084	505
2022-23	8,242	1,870	(8,974)	44,190	530
2023-24	39,619	26,674	14,694	42,042	653
2024-25	12,962	13,275	7,365	35,262	648

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा संकलित

*एनए: उपलब्ध नहीं है